

# सैनिक कमांडरों के संयुक्त सम्मेलन में प्रधानमंत्री का भाषण

नई दिल्ली

18 अक्टूबर, 2006

सबसे पहले मैं उन जवानों और अफसरों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहूंगा जो हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं। मैं पूरे राष्ट्र की ओर से भी आप सभी के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। एक वर्ष पहले जब मेरी आपसे बात हुई थी, उसके बाद सशस्त्र सेनाओं ने लेबनान में फंसे हुए भारतीयों को निकालने में मदद की है और गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और जम्मू कश्मीर में राहत कार्य किए हैं और उस विश्वास को कायम रखा है, जो हमारे राष्ट्र का हमारी बहादुर सशस्त्र सेनाओं में है।

एक साल पहले जब आपसे मेरी बात हुई थी, तो मैंने भारत के आधुनिकीकरण के काम में सशस्त्र सेनाओं की भूमिका की चर्चा की थी। उभरती विश्व व्यवस्था में हमारी सुरक्षा नीति हमारे राष्ट्रीय उद्देश्य और शांति तथा सुरक्षा के लिए हमारी तलाश का प्रतीक है, जिसके अंतर्गत हमने भारत को आर्थिक, सामाजिक और औद्योगिक दृष्टि से मजबूत बनाना है। हमारी सुरक्षा के लिए इस समय जो चुनौतियां मौजूद हैं उनसे निपटने के लिए पर्याप्त रक्षा क्षमता और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी का विकास करना महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही महत्वपूर्ण सामरिक साझेदारी समझौते करना भी आवश्यक है, जिससे हमारी नीति संबंधी पहलुओं का विस्तार होता है और विकास की हमारी संभावनाएं बेहतर होती हैं। यही व्यापक संदर्भ और ऊंचे लक्ष्य हैं, जिनसे हमारे रोजमर्रा के फैसले निर्देशित होने चाहिए।

हम आज ऐसी स्थिति में हैं, जिसमें राष्ट्रीय हितों के लिए समन्वित दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है, जिसमें राजनीतिक, आर्थिक, सैनिक और अन्य पहलू शामिल हैं।

कुल मिलाकर आज विश्व में स्थिति ऐसी है कि अप्रत्याशित आर्थिक अवसर है और इसके साथ ही अप्रत्याशित राजनीतिक खतरे भी हैं। इसी में से होकर आगे चलने के लिए बहुत ही ऊंचे दर्जे की व्यावहारिक नीति और व्यवस्था जरूरी है।

इस दृष्टि से आज राष्ट्रीय सुरक्षा नीति बनाना बहुत बड़ी जटिल बौद्धिक चुनौती है। यह जटिलता और भी ज्यादा है, क्योंकि हम अपने लक्ष्यों को बहुत तेजी से बदलते हुए परिदृश्य में प्राप्त करना चाहते हैं। आर्थिक, सांस्कृतिक और अन्य बहुत से असैनिक क्षेत्रों में विश्व आज ध्रुवीय स्थिति की तरफ जा रहा है, यहां तक कि राजनीतिक शक्ति भी और अधिक अस्पष्ट होती जा रही है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बड़ी शक्तियां विश्व में शक्ति के वितरण की पुनर्व्यवस्था कर रही है। प्रौद्योगिकी के कारण राज्य-शासन से अलग कई ऐसे तत्व हैं जो इस हद तक शक्तिशाली हो गए हैं कि कई देशों में आतंकवाद सीमा पार से प्रमुख खतरा बन गया है।

इसी प्रकार विज्ञान के विस्तार से विनाशकारी हथियारों का निर्माण होने लगा है, जैसा कि पिछले दिनों उत्तर कोरिया के परीक्षण से जाहिर होता है। इससे क्षेत्रीय शक्ति संतुलन में परिवर्तन हो रहा है और अन्य क्षेत्रों को भी इसके परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। सुरक्षा की बदलती चुनौतियों में परम्परागत खतरों के अलावा अराजकतावादी विचारधाराएं, विभिन्न प्रकार के सम्प्रदायवाद और आतंकवाद जैसे खतरे शामिल हैं।

अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद बहुसमुदायी और लोकतंत्रीय समाजों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इससे न केवल जान माल का नुकसान होता है, बल्कि लोकतंत्रीय मूल्यों, सामाजिक सौहार्द और आर्थिक कल्याण के लिए भी खतरा पैदा होता है। आतंकवादी अत्यधिक आधुनिक किस्म के साधनों का उपयोग करने लगे हैं, जिसका परिणाम मौतें और विनाश है। हमारी सशस्त्र सेनाओं को दुर्गम स्थानों पर भी विद्रोहियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए अब यह जरूरी हो गया है कि हम अपनी क्षमताओं को उन्नत करें, जो पहले परम्परागत खतरों से निपटने के अनुरूप रही हैं। इसके साथ ही हमें अपनी निगरानी व्यवस्था को भी मजबूत करना होगा।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमने दृढ़ रवैया अपनाया है कि आतंकवाद के साथ निरंतर और व्यापक स्तर पर लंबी लड़ाई चलेगी। किसी क्षेत्र, धर्म या संगठन की दृष्टि से इसके साथ तदर्थ आधार पर या अलग-अलग हिस्सों में नहीं लड़ा जा सकता है। देश जो कार्रवाई करते हैं या गलतियां करते हैं, आतंकवादी उन्हीं के कारण अपना जाल फैलाते हैं। हमारी रणनीति केवल आतंकवादी कार्रवाइयां करने वालों तक सीमित नहीं रह सकतीं, बल्कि हमें उन देशों के व्यवहार को भी बदलने पर जोर देना होगा, जहां आतंकवादियों को शरण और सहायता मिलती है।

विभिन्न देशों के बीच परस्पर निर्भरता का तेजी से विस्तार हुआ है। यह विडंबना की बात है कि जिस संचार और सूचना प्रौद्योगिकी ने आतंकवाद को एक अंतर्राष्ट्रीय खतरा बना दिया है, उसी ने ही अंतर्राष्ट्रीय पूंजी और विचारों की सीमायें समाप्त कर दी हैं।

इस जटिल स्थिति से निपटने के लिए और अपने राष्ट्रीय हितों को सुनिश्चित करने के लिए अपनी रणनीति को फिर से तय करना हम सबके सामने एक बड़ी चुनौती है। मतलब यह कि नई नीति के अंतर्गत हमें बड़ी शक्तियों के साथ अपने संबंधों और अपने आसपास के पड़ोसियों के साथ संबंधों को फिर से तय करना होगा।

अपनी विशेष स्थिति के अनुरूप आधुनिक भारत के निर्माण के लिए शांति और खुशहाली जरूरी है। मैंने अक्सर कहा है कि दक्षिण एशिया के देशों की मिली जुली नियति है। कुछ हद तक हम ऐसी भावनाओं का विकास कर सकते हैं, अगर हम अपनी आर्थिक समृद्धि में अपने पड़ोसियों को भी शामिल करें। इसके लिए हमें अपनी घरेलू नीतियों में आवश्यक परिवर्तन करने के लिए तैयार रहना होगा।

वास्तविकता यह है कि हम एक खतरनाक और अस्थिर पड़ोस के साथ रह रहे हैं। इस उपमहद्वीप में ही विकास की स्थिति एक जैसी नहीं है, तभी ऐसे परिणाम निकल रहे हैं। हम यह नहीं सोच सकते कि यह देश नाकामयाब रहें। इस क्षेत्र में राजनीतिक अस्थिरता और मानव विकास पर ध्यान देना हमारे हित में है।

हमने पाकिस्तान के सामने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक पाकिस्तान की सरकार आतंकवाद के मुद्दे के साथ स्पष्ट रूप से नहीं निपटती, भारत में किसी भी लोकतंत्रीय सरकार के लिए बकाया मुद्दों को हल करने के लिए बातचीत के मौजूदा रास्ते पर चलना मुश्किल होगा। भारत-पाकिस्तान आतंकवाद-रोधी संस्थागत व्यवस्था पाकिस्तान के उन आश्वासनों को लागू करने के लिए उसके इरादों और क्षमताओं की परीक्षा होगी, जो वह जनवरी, 2004 से देता रहा है।

भारतीय बाजार बंगलादेश वासियों के लिए भारत आने का आकर्षण है, लेकिन इसके साथ ही हमारे उन दुश्मनों को भी मौका देता है, जो आंतकवाद को भारत में भड़काना चाहते हैं। इसके लिए बंगलादेश और भारत दोनों को आपसी सहयोग का तरीका निकालना होगा, जिससे कि हाल के आर्थिक विकास से दोनों देशों के लोगों को लाभ हो। इससे आर्थिक असंतुलन कम होगा। इसके कारण हमारी बंगलादेश के साथ कुछ मुश्किलें हैं।

श्रीलंका में पिछले दिनों गृहयुद्ध का विस्तार हुआ है और अभी भी स्थिति स्पष्ट नहीं है कि श्रीलंका की समस्याओं के संघीय हल के लिए सार्थक बातचीत करने के अपने इरादों में दोनों पक्ष कामयाब होंगे या नहीं।

चीन के साथ सीमा विवाद मुद्दे पर और शांतिपूर्ण विपक्षी संबंधों में आपसी विश्वास पैदा करने में हमने अच्छी शुरुआत की है। हाल की यात्राओं से चीन के साथ हमारे बहुआयामी संबंधों को एक और आयाम मिला है। जिससे यह ऐहसास जगा है कि तेजी से विकसित होते और बदलते समय में दोनों राष्ट्रों को एक दूसरे के साथ मिलकर चलने की जरूरत है।

हमारी सुरक्षा नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू हमारे सीमा क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का तेजी से विकास होना चाहिए। यह महसूस किया जा रहा है कि इसके कई बड़े परिणाम होंगे, न केवल हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए बल्कि बाहरी सुरक्षा की दृष्टि से भी शक्ति में वृद्धि होती है। हमारी सुरक्षा नीति के इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में हमारी विशाल सीमाओं के लिए सेना की केन्द्रीय भूमिका है।

पिछले कुछ वर्षों में भारत में जो परिवर्तन आया है उससे यह स्पष्ट हो गया है कि विश्व के साथ हमारी परस्पर निर्भरता काफी बढ़ी है, हमारी संचार लाइनों की सुरक्षा बहुत जरूरी है। यह केवल समुद्री गतिविधियों तक सीमित नहीं है, जिनका संबंध हमारे विदेश व्यापार और आयात से है, बल्कि विश्व के साथ अन्य तरीकों से हमारे संपर्क भी शामिल है। समान विचार वाले देशों और समुद्र तट से लगे हुए देशों के साथ सुरक्षा क्षेत्र में सहयोग की सक्रिय प्रक्रिया के बिना उसमें से कुछ भी संभव नहीं है।

जब हम अपने विस्तृत पड़ोस को देखते हैं, तो यह देखकर विचित्र स्थिति सामने आती है कि भूमध्य सागर और प्रशांत महासागर के बीच भारत ही एक ऐसा बहुसमुदायी लोकतंत्रीय समाज है, जहां बाजार अर्थव्यवस्था का तेजी से आधुनिकीकरण हो रहा है। इससे न केवल हम पर अपने मूल्यों की रक्षा की जिम्मेदारी आती है बल्कि अपने आसपास के क्षेत्र में शांति के प्रयासों की भी जिम्मेदारी आती है। अब तक हम अपनी सुरक्षा को सिर्फ अपनी आपसी गतिविधियों को बढ़ाने की परम्परागत दृष्टि से देखते रहे हैं। आज चाहे वो पश्चिम एशिया क्षेत्र हो या खाड़ी क्षेत्र, या मध्य एशिया हो या हिंद महासागर क्षेत्र, हमारी राजनीतिक, आर्थिक और रक्षा संबंधी गतिविधियों की सहायता की मांग बढ़ रही है।

भारत पर यह जो नई जिम्मेदारी आ गई है, सरकार के तौर पर हम इसे निभाने को तैयार हैं। उदाहरण के लिए अफगानिस्तान में सुरक्षा और विकास संबंधी जो मुद्दे हैं, उनके लिए हमें नये और रचनात्मक हल चाहिए। अफगानिस्तान में हम वहां लोगों की सहायता करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे तालिबानियों और उनके समर्थक प्रायोजकों में प्रतिक्रिया पैदा हो रही है, जो घड़ी की सूइयों को अभी भी वापस मोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं।

इन नई जिम्मेदारियों को निभाने के लिए हमें देश की क्षमता को बढ़ाना होगा। हमारी सशस्त्र सेनाएं इस क्षमता का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के जटिल स्वरूप को देखते हुए हमें अपनी रक्षा क्षमता का संतुलित विकास सुनिश्चित करना होगा। हमें नौसेना, जल सेना, वायु सेना में आधुनिकीकरण की आवश्यकता है। हमारी जो नई रक्षा नीति विकसित हो रही है, उसकी जरूरतों के मुताबिक अपनी तीनों सेनाओं के उचित स्तर तक विकास के लिए हमें आधुनिकीकरण की एक रणनीति बनानी होगी। आधुनिकीकरण करते समय हमें न केवल स्वदेश में ही साजो-सामान बनाना होगा, बल्कि बाहर से भी मंगाना होगा।

विश्व के साथ और विशेष रूप से आसपास के क्षेत्र के साथ अपने बढ़ते आर्थिक संबंधों और अपनी ऊर्जा सुरक्षा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी नौसैनिक सुरक्षा बढ़ानी होगी। हमारी सामरिक नीति में सामुद्रिक सुरक्षा का महत्व बढ़ता जा रहा है। उच्चस्तर की वायुसैनिक क्षमता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है ताकि जब जरूरी हो, हम सही आकलन और तेजी के साथ कार्रवाई कर सकें।

यदि हम व्यापक राष्ट्रीय दृष्टि से 21वीं शताब्दी में अपनी राष्ट्रीय क्षमता के पहलुओं पर गौर करें, तो हमें अपनी आर्थिक, औद्योगिक और रक्षा आवश्यकताओं को एकीकृत करने के लिए नये-नये और ठोस तरीके ढूंढने होंगे। रक्षा मंत्रालय ने इसके लिए हाल में कुछ कदम उठाए हैं। इनमें से एक कदम रक्षा खरीद में पारदर्शिता रखने का है, जिसके लिए रक्षा खरीद प्रक्रिया 2006 शुरू की गई है। दूसरा, कदम उन दीर्घावधि प्रस्तावों के बारे में है, जिनके लिए देश के अंदर ही प्रयास किए जा सकते हैं। इससे भारतीय उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। तीसरा कदम, खरीद सौदों के लिए नई रक्षा आफसेट नीति है।

खरीद सौदों में पारदर्शिता, अच्छे प्रशासन और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों देशों के लिए उचित है। इन प्रक्रियाओं की आलोचना से संबंधित रिपोर्टों से, यदि वे गलत हैं तो सेना का मनोबल गिर सकता है और यदि वे सही हैं तो उनपर सीधे ध्यान देने की जरूरत है।

विचारों में, योजना में, और कार्यवाही में संयुक्त प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए उठाए जा रहे कदमों की मैं सराहना करता हूँ। जैसे-जैसे हम अपने नौसेना और वायुसेना में और अधिक निवेश करते हैं, एक आधुनिक और सुसज्जित नौसेना और वायुसेना का विकास करते हैं, उन कदमों का महत्व और बढ़ जाता है। तीनों सेनाओं को अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए और कार्रवाई के दौरान अधिक से अधिक प्रभाव छोड़ने के लिए मिलकर काम करना चाहिए।

भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय (आईएनडीयू) और भारतीय सशस्त्र सेनाओं के लिए संयुक्त सिद्धांत-नीति का परिणाम संयुक्त प्रशिक्षण और संयुक्त कार्रवाई होना चाहिए। इस विश्वविद्यालय को सामरिक नीति विश्लेषण और नियोजन को बढ़ावा देने के लिए उत्प्रेरक बनना चाहिए। दीर्घावधि सामरिक चिंतन के विकास में इसका योगदान होना चाहिए।

भारत आज बाकी विश्व के साथ काफी हद तक जुड़ा हुआ है, और इसके लिए इसके पास काफी क्षमता है। यदि हमारी अर्थव्यवस्था का विकास जारी रहता है तो मुझे विश्वास है कि हम साजो सामान और अन्य उद्देश्यों के लिए अपनी सशस्त्र सेनाओं की जरूरतों को पूरा करने के तरीके ढूंढ सकते हैं। यदि हमारे लक्ष्य बढ़े हैं, तो हमारे साधन भी बढ़े हैं। प्रत्यक्ष बाहरी खतरों के मुकाबले आंतरिक सुरक्षा आज हमारे ये कदम अधिक चिंता का विषय है।

असल में यह बड़े बाहरी खतरे का मूर्तरूप ही है, जो हम आंतरिक सुरक्षा के प्रति खतरे के रूप में देखते हैं, जैसा कि जुलाई में हमने मुंबई में देखा।

आज हमारे सामने चुनौती है कि हम इस तेजी से बदलती स्थिति में कैसी बुद्धिमता दिखाते हैं। हमारी सरकार सशस्त्र सेनाओं की आवश्यकताओं को, चाहे वो उपकरणों या आपूर्ति या सेवा से संबंधित मुद्दों के मामले में हो, प्राथमिकता देती रहेगी। अंत में मैं एक कृतज्ञ और गौरवान्वित राष्ट्र की ओर से आप सबके पेशेवराना दृष्टिकोण और समर्पण की भावना के लिए आप सबको बधाई देता हूँ।

जय हिंद!

\*\*\*\*\*